

an>

Title: Need to revise the sugar policy to address the problems of The sugarcane farmers and sugar industry.

**श्री राजू श्रेष्ठ (हलकणंगले) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले तीन-चार वर्षों से चीनी और गन्ना उत्पादन ने देश के किसानों ने सत-दिन अथक प्रयास से एक नई ऊंचाई प्राप्त की है तो दूसरी ओर घरेलू बाजार में चीनी के घटते हुए मार्केट रेट की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है।

पिछले तीन-चार वर्षों के मुकाबले चालू वर्ष में तो चीनी की दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है जबकि दूसरी ओर गन्ना उत्पादक किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) भी कुछ चीनी मिलों को छोड़कर नहीं दे पाई है। इस वजह से आज आर्थिक संकट के कारण कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की बकाया शक्ति बढ़ गई है जिससे देश भर की चीनी मिलों को गन्ना किसानों की कम से कम एफआरपी देने के लिए तत्कालीन प्रयास के तौर पर 6,000 करोड़ रुपए की शक्ति बिना ब्याज का लोन पैकेज घोषित करना पड़ा। आज की स्थिति में सरकार ने 10 प्रतिशत एथनॉल का इस्तेमाल करना पेट्रोलियम कंपनियों को अनिवार्य किया है। यदि मांग और आपूर्ति की ओर देखा जाए तो चीनी मिलें एथनॉल निर्माण में ठीक सी प्रतिक्रिया देती नहीं दिख रही हैं इसलिए केंद्र सरकार को दीर्घकालीन योजना ताने की जरूरत है। इसमें प्रथम, तत्काल 40 लाख टन कच्चा चीनी निर्यात करने का निर्णय लेना चाहिए जिससे मांग और आपूर्ति का अनुपात बराबर रहेगा और इससे चीनी के दाम स्थिर रहेंगे। द्वितीय, एथनॉल का उत्पाद और इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना और आगे चीनी उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए ब्राजील की भांति गन्ने के जूस से सीधे एथनॉल का निर्माण और इसके साथ-साथ 50 प्रतिशत चीनी और 50 प्रतिशत एथनॉल का उत्पादन करने वाले नए चीनी उद्योग को नई तकनीक से सजा करना। तृतीय, चीनी और ड्यूएल प्रोडक्शन पॉलिसी और बफर स्टॉक, चौथा, गन्ने के बीज प्रोडक्ट्स और बिजली के ऊपर ध्यान। पांचवां, गन्ना प्लांटेशन को घटाकर ऑयल सीड और पत्तेज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकनॉमिक इंसेटिव्स और उत्तम दरों की गारंटी अगर सरकार किसानों को देती है तो किसान गन्ने की खेती की तरफ ध्यान देंगे और इससे चीनी उद्योग के सामने जो अस्थिरता का संकट सजा हो गया है, उसे दूर करने में किसान चीनी उद्योग के मददगार साबित होंगे।

**15.00 hrs**